



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940

No. 439]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

का.आ. 552(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (दिल्ली के सिवाय गोवा राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए) भारत सरकार द्वारा गठित आयोग, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

- (क) याचिका फीस;
- (ख) लाइसेंस फीस; और
- (ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) से अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (दिल्ली के सिवाय गोवा राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए):—

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के बारे में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2019/फा. सं. 300196/17/2016-आईटीए-I]

राजराजेश्वरी आर., अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2019

S.O. 552(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories except Delhi)', a commission constituted by the Government of India, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:—

- (a) Petition fees;
- (b) Licence fees; and
- (c) Interest earned on (a) and (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories except Delhi)—

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2017-2018 and 2018-2019 and shall apply with respect to the assessment years 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022.

[Notification No. 6/2019/F. No. 300196/17/2016-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.

Explanatory Memorandum : It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.